निर्मला सीतारमण ने 7वां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया

हिन्दी साप्ताहिक

हर्षिता टाइम्स

RNI Regn. No. UTTHIN/2008/28646

कांवर यात्रा के दौरान, भगवान शिव के भक्त हर की पौड़ी, हरिद्वार से गंगा नदी का पवित्र जल इकट्ठा करते

• वर्ष : 16 • अंक : 29 • देहरादून • वृहस्पतिवार 25 जुलाई, 2024 • मूल्य : 1 रुपये • वार्षिक : 50 रुपये • पृष्ट : 4

विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में नई दिशा और गति प्रदान करेगा बजट- मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आम बजट 2024-25 को लेकर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह बजट भारतवासियों की आकांक्षाओं को साकार करेगा व देश को नई दिशा और गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट सदन के पटल पर रखा है। वह ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा करने हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण चार शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को और मज़बूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गत वर्ष हुई ग्लोबल इनवेस्ट समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से उत्तराखण्ड को लाभ मिलने की आशा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट थीम में रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बजट में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। उन्होंने

कहा कि बजट में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया गया है। इससे, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ⋆10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्य फसलों पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया है जो भारत के समग्र विकास को सशक्त करने कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गत वर्ष हुई ग्लोबल इनवेस्टर समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से उत्तराखंड को लाभ मिलने की आशा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट थीम में रोजगार, स्किलिंग, डैडम, मिडिल क्लास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बजट में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया गया है। इससे, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ⋆10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्य फसलों पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बड़कोट क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान का दिया आश्वासन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में सायं बड़कोट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में वर्णित समस्याओं के समाधान पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं।

इस अवसर पर ज़िलाध्यक्ष बीजेपी सतेंद्र राणा, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, पूर्व ज़िलाध्यक्ष जयवीर सिंह जयारा, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा चण्डी प्रसाद बेलवाल, मण्डल अध्यक्ष जयप्रकाश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के प्रयासों से कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड कैशलेश इलाज की सुविधा

देहरादून। बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति गोल्डन कार्ड की सौगात मिल गयी है। बीकेटीसी के केनाल रोड कार्यालय सभागार में अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड सौंपे। इस अवसर पर कार्मिकों ने बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र का गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु किये प्रयासों की सराहना की और आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि बीकेटीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के पश्चात अजेंद्र ने अपने कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इसके लिए दिसंबर 2022 में सम्पन्न हुई मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मंदिर समिति कर्मचारियों के लिए भी गोल्डन कार्ड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद कार्मिकों का विवरण जमा कर गोल्डन कार्ड बनवाने का कार्य शुरू

हुआ। अब तक डेढ़ सौ से अधिक कार्मिकों के गोल्डन कार्य बनकर तैयार हो गए हैं। पेंशनर्स के भी गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।

यही नहीं अस्थायी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) सहित पीएफ का लाभ दिये जाने हेतु बीकेटीसी द्वारा प्रयास किये जा रहे है। इस संदर्भ में कार्यवाई अंतिम चरण में है।

गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य वित्त अधिकारी आनंद सिंह, अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी, सहायक अभियंता विपिन तिवारी, विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल, पूर्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल, निजी सचिव प्रमोद नौटियाल, प्रबंधक अनसुया नौटियाल, प्रबंधक किशन त्रिवेदी, आशुतोष शुक्ला, मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़, प्रबंधक विशाल पंवार, संजय चमोली, दीपेंद्र रावत, कल्पेश्वरी देवी, विनोद नौटियाल, अमित देवराड़ी, राहुल नेगी, सचिन सेमवाल, एकता, पिंकी, रीना, सविता, विजय पंत, सचिन कुमार आदि मौजूद रहे

सम्पादकीय

राजकोषीय मजबूती और राजनीतिक संतुलन

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते समय उस राजनीतिक संदर्भ का जिक्र नहीं किया, जिसमें उनके मंत्रालय को बजट तैयार करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस नई सरकार के समक्ष पहले की तुलना में अधिक चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टर समर्थकों से चुनाव में सरकार को मिले कड़े संदेश के बाद उस पर दबाव काफी बढ़ गया था।

मगर सीतारमण एवं उनकी टीम ने इन राजनीतिक विवशताओं और सरकार की प्राथमिकताओं, विशेषकर राजकोषीय मजबूती के बीच संतुलन साध कर सराहनीय कार्य किया है।

मगर बजट में इसमें किसी तरह का इजाफा करने के बजाय इसे संशोधित कर 4.9 प्रतिशत कर दिया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने वादा किया कि अगले वर्ष तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत से नीचे रह जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से मिले 2.1 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम लाभांश की मदद से बजट आंशिक रूप से राजकोषीय समझबूझ के मोर्चे पर बेहतर साबित हुआ। फरवरी में अंतरिम बजट में लाभांश के अनुमान से सरकार को लगभग दोगुना रकम मिली।

राजकोषीय मोर्चे पर संयम जरूर दिखाया गया है मगर इससे व्यय की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होने दी गई है। पूंजीगत व्यय को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। राजस्व व्यय में बढ़ोतरी कुल व्यय की तुलना में थोड़ी कम रही है। दिलचस्प है कि पूंजीगत व्यय में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा राज्यों को भी आवंटित किया जाएगा।

हालांकि, यह रकम राज्यों को इस शर्त पर दी जाएगी कि वे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले सुधार करेंगे। हालांकि, इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पहले से चला रहा तनावपूर्ण संबंध और बिगड़ जाएगा।

दूसरी तरफ, सुधार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पास सीमित विकल्प हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार इन सभी विकल्पों को आजमाएगी। सरकार उन मामलों में रकम खर्च करने में सतर्क रही है जहां सश्वरिन या सरकार की गारंटी पर्याप्त होती है। सरकार राज्य सरकारों को साथ लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का सहारा लेती रही है। ऐसा सूझ-बूझ वाला वित्तीय प्रबंधन सब्सिडी के आंकड़ों में भी साफ तौर पर परिलक्षित होता है।

सरकारी खरीद में कमी लाने से खाद्य सब्सिडी मद में व्यय कम हुआ है। भारत में राजकोषीय गणित तैयार करने में खाद्य सब्सिडी एक बड़ी समस्या रही है मगर अब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसकी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हो रही है। रोजगार की कमी एक अन्य बड़ी राजनीतिक बाधा रही है मगर इससे कभी सावधानी से नहीं निपटा गया।

उदाहरण के लिए बजट में 'इंटर्नशिप' योजना की घोषणा पूरी तरह सोच-समझकर नहीं की गई है। अगर यह योजना मूल स्वरूप में ही लागू हुई तो इससे मानव संसाधन नीतियों एवं निजी क्षेत्र में उथल-पुथल मच जाएगी। इससे संरक्षण एवं अक्षमता बढ़ जाएगी। इन पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता आन पड़ सकती है।

बाजार ने बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। वित्त मंत्री ने दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है और लघु अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर भी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। वायदा एवं विकल्प कारोबार लेनदेन पर कर दरें बढ़ा दी गईं। हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया से इतर इन बदलाव के आधार मजबूत हैं।

करों में बदलाव पर कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं इसलिए आई हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में प्रत्यक्ष करों की राह कैसी होगी। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे पर बजट में उत्साहजनक वादा जरूर किया गया है मगर घाटे एवं कर्ज पर लक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। इस पर स्थिति साफ होती तो काफी मदद मिली होती।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार पहुंचे हरिद्वार

हरिद्वार। मेला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अभिनव कुमार द्वारा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण के साथ बैरागी कैंप, सिंह द्वार, शंकराचार्य चौक, बस अड्डा, ज्वालापुर, नीलधारा पार्किंग, रोड़ी बेलवाला, हर-की-पैड़ी एवं अन्य मेला क्षेत्रों का भ्रमण/स्थलीय निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति पर मंथन उपरांत व्यवस्थाओं को और बेहतर किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया।

इसके पश्चात डीजीपी उत्तराखण्ड द्वारा सीसीआर (मेला कंट्रोल रूम) में समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर अपने लंबे अनुभव को साझा करते हुए विगत वर्षो में कांवड़ यात्रा में पेश आई समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण, वर्तमान पुलिस के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां एवं अन्य विभागों से बेहतर तालमेल अनेकानेक छोटी-बड़ी समस्याओं के सुगमतापूर्वक समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

साथ ही अवगत कराया की यह कांवड़ मेला हमारे लिए एक चैलेंज है जिसमें हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारियां के साथ मुस्तैद रहकर निभाना है।

इस दौरान अभिनव कुमार द्वारा कावड़ मेला प्रभारी को निर्देशित किया कि ड्यूटीरत सभी कर्मियों को बरसाती उपलब्ध करा दी जाए एवं खाने-पीने एवं रहने की कोई भी समस्या हो तो उसे दूर किया जाए।

सभी जोनल एवं सुपर जनरल प्रभारी से एक-एक कर परिचय प्राप्त करते डीजीपी उत्तराखंड द्वारा उनसे क्षेत्र एवं ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारीगण की पूरी जानकारी लेते हुए उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना के संबंध में भी निर्देशित किया गया।

सभी जोनल प्रभारी को अवगत कराया गया कि जब शिफ्ट चेंज होती है तो प्रतिस्थानी कर्मचारी के अपने पॉइंट तक पहुंचने तक ड्यूटी प्वाइंट न छोड़ा जाए।

जोनल एवं सेक्टर प्रभारी अपने-अपने जोन सेक्टर में ही यथावत बने रहेंगे। कोई भी आवश्यकता होने पर मेला कंट्रोल रूम से संपर्क कर मदद प्राप्त करेंगे। ड्यूटी में किसी भी रैंक के अधिकारी से लापरवाही की आशा नहीं करूंगा।

पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया की डाक कावड़ के दौरान दुपहिया वाहन जो रोड में डिवाइड लगे होते हैं उन्हें तोड़कर या लांघकर दूसरी तरफ आ जाते हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ अव्यवस्था बन जाती हैं, जो पुलिस के लिए काफी चुनौती बन जाता है। सड़क मार्ग पर ड्यूटी करने वाली विशेषत इस पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा न हो।

मीटिंग के बाद डीजीपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कावड़ मेले के प्रथम दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस /पैरामिलिट्री/ होमगार्ड के 9 लोगों को पुरुस्कृत किया गया। आगे भी प्रतिदिन उत्कृ ट कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता रहेगा।

तत्पश्चात डीजीपी एवं अन्य अधिकारी गण द्वारा सांयकालीन मां गंगा आरती दर्शन करते हुए कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मां गंगा से प्रार्थना की गईसस

बैठक के दौरान एडीजी अमित सिन्हा, एडीजी लॉ एण्ड ऑर्डर ए.पी. अंशुमन, आई.जी. अभिसूचना के.के. वीके, आई. जी. रेंज करन सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, सरिता डोभाल पुलिस अधीक्षक जीआरपी व सभी जोनल एवं सेक्टर पुलिस अश्वफिसर्स उपस्थित रहे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों की मुलाकात

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को उनके तीन साल के कार्यकाल की सफलता पर बधाई दी और कैबिनेट द्वारा राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट या समिति गठित करने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया।

महापंचायत के पदाधिकारियों ने चारधाम के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और मेलों के आयोजन के लिए राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों, मंदिर समितियों और अन्य हितधारकों को विश्वास में लेने का अनुरोध किया। उन्होंने यात्रा के दौरान वीडियो और अपुष्ट जानकारी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त करने की भी मांग की ताकि कोई भी तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट या समिति गठित करने के विरुद्ध कड़े विधिक प्रावधान किए जाने से किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने और आने वाले 30 वर्षों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन की योजना बना रही है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों की राय ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में दोनों व्यवस्थाएं खुली रहेंगी ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, चारधाम महापंचायत के महासचिव डॉ. बृजेश सती, यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल, मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल, उपाध्यक्ष अमित उनियाल, गंगोत्री धाम के आलोक सेमवाल, लखन उनियाल, सुरेश हटवाल, रमेश कोठियाल, चिंतामणि हटवाल, गौरव, हार्दिक, शिवम, सुशील और डॉ. मनीष सेमवाल आदि उपस्थित रहे।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ : सुरेश भट्ट

देहरादून। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखण्ड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट जनपद देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री भट्ट ने जनपद में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये।

बैठक में उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने कहा कि समुदाय स्तर पर आयुष्मान कार्ड तथा उसके अंतर्गत मिलने वाले पैकेज व सूचीबद्ध चिकित्सालयों की सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। आशा कार्यकत्रियां समुदाय स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य कार्यकत्री हैं, उनके कार्य से संबंधित इंसेंटिव समय पर निर्गत करें।

उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा जन औषधि केन्द्रों में उपलब्ध दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो कि जनहित में है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा लाभार्थीपरक योजनाओं की जानकारी जनता तक जानी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले सके। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और धरातल पर स्वास्थ्य सेवाओं में समानता होनी चाहिए। लाभार्थियों की संतुष्टि ही सबसे बेहतर आंकड़े हैं।

बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन.एच.एम. डॉ. निधि रावत ने कार्यक्रमवार सभी योजनओं की प्रगति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। जिला वरिष्ठ क्षय रोग अधिकारी डॉ. मनोज वर्मा ने निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड में टी.बी. रोग के इलाज को सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया।

समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय जैन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्मिक डॉ. वंदना सेमवाल, डॉ. सीएस रावत, डॉ. दिनेश चौहान, डॉ. केएस भण्डारी, डॉ. विक्रम तोमर, डॉ. प्रदीप उनियाल, डॉ. यतेन्द्र सिंह, डॉ. घिल्डियाल, डॉ. पीएस रावत, डॉ. मोहन डोगरा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक लक्ष्मण सिंह रावत, सिटी अर्बन हेल्थ ऑफिसर राकेश बिष्ट, जिला लेखा प्रबंधक विवेक गुसाई, जिला सलाहकार एनटीसीपी अर्चना उनियाल सहित समस्त एनएचएम कर्मियों ने प्रतिभाग किया।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने सहकारी समितियों के ग्राम स्तर के कार्यों में तेजी लाए जाने के दिए निर्देश

देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग के नए सचिव दिलीप जावलकर की मौजूदगी में सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के ग्राम स्तर के कार्यों में तेजी लाई जाय और चल रही योजनाओं का निरीक्षण एवं प्रभावी ढंग से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना निदेशालय में समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. रावत ने ग्राम स्तर की सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि वे स्थानीय किसानों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हों। उन्होंने सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं को अपने ग्राम स्तर के कार्यों में तेजी लाने तथा चल रही योजनाओं का समयबद्ध एवं कुशल तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने निर्देश दिया कि सहकारी बैंकों में राज्य सरकार का शेयर का प्रावधान करेगी। राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक प्रोफेशनल एमडी होंगे। एमपैक्स सचिवों की नियमावली कैबिनेट में रखे जाने के निर्देश दिए गए है। सहकारी बैंकों में ट्रांसफर नीति बनाने पर भी समीक्षा की गई। मंत्री ने नेट बैंकिंग की प्रगति भी जानी। राज्य सहकारी बैंक के एमडी ने बताया कि पिछले साल सहकारी बैंकों का 66 करोड रुपए प्रॉफिट था जबकि इस साल 115 करोड रुपए प्रॉफिट हो गया है।

उन्होंने बताया गया कि राज्य के 52 प्रगतिशील किसानों को पिछले साल गुजरात और हिमाचल का भ्रमण कराया गया था। जहां उनका अध्धयन संतोषजनक रहा। मंत्री डॉ. रावत ने पीसीयू के एमडी को निर्देश दिए कि इस साल पांच राज्यों जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, केरल का अध्ययन भ्रमण की रूपरेखा सुनिश्चित करें। इस भ्रमण में किसानों के साथ शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे।

रेशम को-ऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी आनंद शुक्ल ने बताया कि राज्य की 6500 महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं फेडरेशन द्वारा निर्मित रेशम के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि पॉल्ट्री फार्मिंग भी राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की लाभकारी योजना है। इससे किसान काफी संख्या में जुड़ रहे हैं।

सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि समीक्षा बैठक में जो विंदु चर्चा हुए हैं तथा सहकारी योजनाओं का लक्ष्य के साथ कार्य करें।

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ, प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तराखंड रेशम फेडरेशन, उत्तराखंड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, उत्तराखंड भेड़ -बकरी एवं शशक फेडरेशन, उत्तराखंड मत्स्य सहकारी संघ, श्रम निर्माण संविदा सहकारी संघ, उत्तराखंड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ, उत्तराखंड साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ, उत्तराखंड मत्स्य सहकारी संघ की समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद शुक्ल, नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, रमिन्द्री मंद्रवाल, पान सिंह राणा, भरत सिंह रावत डॉ. मनोज शर्मा, आदि अधिकारी मौजूद थे।

नीतीश कुमार को झटका, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

नई दिल्ली। लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती आ रही है। मानसून सत्र के दौरान जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने सरकार से सवाल किया जिसपर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने साफ कहा कि बिहार स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में फिट नहीं है।

संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में जहां एक प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठायी।

इससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी द्धभाजपाऋ के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठायी गयी थी। लोकसभा में जनता दल (यू) के सदस्य रामप्रीत मंडल ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार है?

इस प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रहीं।

उन्होंने कहा कि 'पूर्व में विशेष श्रेणी के दर्जे के बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आईएमजी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।' वर्ष 2012 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार केंद्र में थी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का किया निरीक्षण

देहरादून। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीरथपाल सिंह ने ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा ग्रीन बिल्डिंग परियोजना के कार्य को समय पर पूरा करने के दिए गए निर्देशों के पालन में किया गया।

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। उन्होंने अधिशासी अभियंता सीपीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्माण कार्य के लिए तुरंत वर्क प्लान सबमिट करने हेतु निर्देश दिए गए। कार्यस्थल पर सभी कार्मिकों को पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) पहनने के निर्देश दिए गए। भवन निर्माण परिसर से सटी बाउंड्री की सुरक्षा का भी जायजा लिया गया। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य के दौरान आसपास स्थित आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कार्य संस्था को कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्रीन बिल्डिंग में फाउंडेशन के लिए राफ्ट में कंक्रीट का कार्य सीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है।

इस निरीक्षण से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ग्रीन बिल्डिंग परियोजना समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो, ताकि देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उत्तराखण्ड का अम्ब्रेला ब्राण्ड होने के साथ स्थानीय महिलाओं की आजीविका का सशक्त माध्यम बनेगा हाउस ऑफ हिमालयाजः मुख्य सचिव

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग, क्वालिटी व ब्राण्डिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने हाउस ऑफ हिमालयाज को उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड के रूप में स्थापित करते हुए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत अधिकाधिक महिला स्वयं सहायता समूहों व स्थानीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड के सभी उत्पादों को एक ही नाम व ब्राण्ड मिलने से राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा।

सीएस ने निर्देश दिए हैं कि हाउस अश्वफ हिमालयाज के माध्यम से राज्य के सभी स्थानीय ब्राण्ड्स की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। हाउस ऑफ हिमालयाज को वॉकल फॉर लोकल तथा लोकल फॉर ग्लोबल की थीम के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर तक पहुचाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज राज्य का अम्ब्रेला ब्राण्ड होने के साथ ही प्रदेशभर की स्थानीय महिलाओं की आजीविका का सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और उनके उत्पादों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत प्रथम चरण में 21 उत्पादों को रखा गया है। भविष्य में अधिकाधिक स्थानीय उत्पादों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तीन स्तरों पर की जा रही है।

सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हाउस ऑफ हिमालयाज की बोर्ड ऑफ गवर्नेस की बैठक में सचिव राधिका झा, अपर सचिव मनुज गोयल सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने किया सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उरेडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना में आवेदन एवं अनुदान निर्गत किये जाने के लिए पोर्टल पद का शुभारम्भ किया गया।

प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट एवं सोलर वाटर हीटर, 27 भवनों पर 1.26 मे.वा. क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट तथा 44 राजकीय भवनों पर स्थापित 48400 लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर सयंत्रों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किये गये तथा 04 संख्या लाभार्थियों को पी0एम0 सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य अनुदान के चेक प्रदान किये गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व पूरे देश में तेजी से बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पांरपरिक जीवाश्म आधारित ईधन के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी और समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। वर्ष 2026 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।

पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य में अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से अब तक 750 विकासकर्ताओं को 133 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट दिये गये हैं। इस योजना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा आधारित प्रदेश उत्तराखण्ड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, एमडी पिटकुल पी.सी ध्यानी, उप महानिर्देशक एनआईसी अशेष कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सचिदानंद दुबे, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेडा मनोज कुमार, उप-मुख्य परियोजना अधिकारी, अखिलेश कुमार शर्मा, संदीप भटट्, वंदना उपस्थित थे।

सिस्टम की गड़बड़ी के कोई ठोस सबूत नहीं, दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे परीक्षा की शुचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है,उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अपनी दलील में कहा है कि ये साफ है कि 4 मई को स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था। उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किए और फिर भी फेल हो गए। पेपर लीक के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है, कम समय में ये हो ही नहीं

सकता।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मंगलवार को नीट यूजी मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा के बीच तल्ख बहसबाजी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकार भी लगाई। दरअसल, नेदुम्परा कथिर तौर पर अधिवक्ता हुड्डा को बीच में रोक रहे थे।

उस वक्त हुड्डा पीठ को संबोधित कर रहे थे और वह एक याचिकाकर्ता की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा से अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा की दलीलें पूरी होने तक इंतजार करने को कहा। मगर वह नहीं रुके और बीच में टोकना जारी रखा। मैथ्यूज ने कहा कि वह सर्वोच्च अदालत के समक्ष सभी वकीलों में सबसे वरिष्ठ हैं।

बीकेटीसी में सुरक्षा और आईटी संवर्ग के 58 नए पद स्वीकृत

देहरादून। शासन ने श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संवर्ग के लिए पदों के सृजन की अनुमति दे दी है। सुरक्षा संवर्ग में 57 व आईटी संवर्ग में एक पद सृजित किया गया है। संस्कृति व धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग का प्रमुख मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहलाएगा। यह पुलिस के उपाधीक्षक रैंक का अधिकारी होगा, जिसे नागरिक पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बल अथवा अर्ध सैनिक बल से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी के नीचे दो मंदिर सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किये गए हैं। यह इंस्पेक्टर रैंक के होंगे। सब इन्स्पेक्टर रैंक के चार उप मंदिर सुरक्षा अधिकारी होंगे। सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।

इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आईटी

संवर्ग के लिए शासन ने बीकेटीसी में सहायक प्रोग्रामर का एक पद सृजित किया है। इस पर नियत मानदेय पर नियुक्ति की जायेगी।

उधर, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी का अपना सुरक्षा संवर्ग होने से मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। आईटी संवर्ग में पदों के सृजन से विभिन्न व्यवस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग होगा। ई-ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग होने से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सुबोध भट्ट द्वारा दून वाणी प्रिंटर्स डी0एल0 रोड, देहरादून से मुद्रित एवं मोहकमपुर कलां, माजरी मी, पो0ओ0 नवादा, देहरादून, उत्तराखंड से प्रकाशित।
सम्पादक : सुबोध भट्ट मो0 9837383994, email : subodhbhatt09@gmail.com
Web site : harshitatimes.com, facebook page : harshitatimes.com, email : harshitatimes09@gmail.com,